सांध्य दैनिक
4PM

शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउन्ट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का।
-डॉ. अब्दुल कलाम

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्षः 11 ● अंकः 198 पृष्ठः 8 ● लखनऊ, सोमवार 25 अगस्त, 2025

जीशान का कमाल, मेरठ ने लहराया... 7 | बंगाल में अभी से लगा चुनावी... 3 | प्रदेश में न खाद है और न किसान... 2

वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी!
जेपीसी का बहिष्कार, विपक्ष का ऐलान

» नये विधेयक पर तनातनी, विपक्ष बोला अब सत्ता चुराना चाहती है बीजेपी

» टीएमसी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल होने से किया मना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। वोट चोरी के बाद विपक्ष ने अब एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी पर सीधे सत्ता चोरी का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये विधेयक को आधार बताते हुए सत्ता चोरी का आरोप जड़ दिया है। उन्होंन कहा है कि अब बीजेपी सीधे सत्ता चोरी करने पर उतर आयी है।

उन्होंने कहा कि अभी तक यह काम गवर्नर के जरिये होता था लेकिन अब वह कानून का सहारा लेकर राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश में लग गयी है। उन्होंने झारखंड, बंगाल और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में बीजेपी सबकुछ करके के भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी तो उसने नया दांव खेला है।

नीतीश-नायडू पर निशाना

दिल्ली की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या सचमुच भारत का लोकतंत्र अब सत्ता चोरी के मुकाम पर पहुँच चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का ताजा बयान पहले वोट चोरी अब सत्ता चोरी सिर्फ एक जुमला नहीं है यह इस बात की गवाही है कि संसद में पेश किए गए नए विधेयक को विपक्ष किस तरह लोकतंत्र की हत्या की दिशा में उठाया गया कदम मान रहा है। यह विधेयक केंद्र को यह अधिकार देने का प्रस्ताव करता है कि वह किसी भी राज्य सरकार के मंत्रियों को महज 30 दिनों के भीतर हटाने या बदलने का रास्ता बना सके। सवाल उठना लाज़मी है कि क्या यह संसद संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्या यह राज्य की जनता के जनादेश की खुली चोरी नहीं होगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह विधेयक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को मैनेज करने की सियासी चाल है।

बुनियादी सोच ही गलतः अखिलेश

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जेपीसी के बहिष्कार के टीएमसी के रूख का समर्थन करते हुए कहा है ?कि इस विधेयक का बुनियादी विचार ही गलत है। कोई भी किसी पर फर्जी केस डाल दे तो विधेयक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। टीएमसी ने बकायदा अधिकारिक बयान में विधेयक पर प्रस्तावित जेपीसी को एक मजाक करार देते हुए साफ कहा था कि पार्टी इसमें अपने सांसदों को नहीं नामित करेगी। इंडिया गठबंधन के अगुवा के तौर पर कांग्रेस जेपीसी बहिष्कार की घोषणा करती है तो मोदी सरकार के अब तक के कार्यकल में यह जेपीसी के विपक्ष की ओर से बहिष्कार का पहला मामला होगा।

ममता ने किया ऐलान

पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना देरी किए विधेयक का मुखर विरोध करते हुए जेपीसी को तमाशा करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी इसी राह पर चलते हुए जेपीसी से किनारा करने की घोषणा कर दी। लोस में सपा के 38 सदस्य तो टीएमसी का संख्या बल 29 का है। इंडिया गठबंधन की लोस में 232 की कुल संख्या में इन दोनों की 67 सांसदों की हिस्सेदारी को देखते हुए कांग्रेस के सामने जेपीसी या घटक दलों में से किसी एक को चुनने की दुविधा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ संसदीय रणनीतकार ने कहा कि विपक्ष के सहयोगी दलो को साथ लेकर चलना हमारी प्राथमिकता है। टीएमसी तथा सपा के एलान के बाद स्वाभाविक रूप से जेपीसी का बहिष्कार करने के सवाल पर पार्टी में विचार मंथन चल रहा है और जरूर इसकी संभावनाएं पुख्ता संभावनाए हैं।

धनखड़ पर शाह के बयान के बाद जयराम रमेश का सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोमवार को दिए गए बयान के बाद कि विपक्ष को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा नहीं करना चाहिए, इस कहानी में और भी कुछ हो सकता है। कांग्रेस नेता ने धनखड़ की मानदंडों, शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने और किसानों के कल्याण तथा न्यायिक जवाबदेही के लिए निडर होकर बोलने के लिए प्रशंसा की। रमेश ने कहा कि आज गृह मंत्री ने और भी कुछ कहने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने केवल रहस्य को और बढ़ा दिया है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों के हितों की वकालत करने वाले अदम्य और उत्साही धनखड़ एक महीने से भी अधिक समय से पूरी तरह से संपर्क से बाहर क्यों हैं। केंद्रीय गृह मंत्री नें कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह घर में नज़रबंद हैं। शाह ने कहा कि धनखड़ साहब का त्यागपत्र अपने आप में स्पष्ट है।

होगा जेपीसी का बहिष्कार

तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नये विधेयक को जेपीसी में भेजने के बाद जेपीसी के बहिष्कार का एलान कर दिया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों की गिरफ्तारी के 30 दिनों के बाद बर्खास्त किए जाने संबंधी विधेयक पर गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का समूचा विपक्ष बहिष्कार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। तृणमूल कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के जेपीसी का हिस्सा बनने से स्पष्ट इनकार के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने भी संकेत दिए हैं कि वह इसमें शामिल नहीं के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है।

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु के लखनऊ पहुंचने पर भव्य स्वागत

» राजधानी की सड़कों पर उमड़ी लोगों की भीड़

» उन्हें राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूकर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का सोमवार अपने शहर लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सुबह शुभांशु शुक्ला लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।

एयरपोर्ट के बाहर स्कूल के बच्चे पहुंचे

एयरपोर्ट के बाहर शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए उस स्कूल के बच्चे तिरंगा झंडा लिए खड़े थे, जहां से उन्होंने भी पढ़ाई की है।

एयरपोर्ट पर खुद उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कैप्टन शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 से लेकर शहर के प्रमुख चौराहों तक, भाजपा कार्यकर्ता और लोग शुभांशु पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। लखनऊ शहर की सड़क पर जब शुभांश शुक्ला का काफिला निकला, तब सड़क के दोनों और उनकी एक झलक देखने को लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।

स्वागत में सड़कों पर खड़े रहे लोग

लखनऊ की सड़कों पर लोग हाथों में तिरंगे झंडे लिए, तालियां बजाकर और फूल बरसाकर शुभांशु शुक्ला का स्वागत कर रहे हैं, जहां से भी शुभांशु शुक्ला का काफिला गुजर रहा है, वहां सड़क के दोनों और खड़े लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिख रहे हैं।

प्रदेश में न खाद है और न किसान सुरक्षित है: अखिलेश

कहा- बदलाव के लिए जनता भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों की दुदर्शा को भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रहे खाद संकट को लेकर भी योगी सरकार को जमकर कोसा है उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। कई जगह खाद की लाइन में लगे-लगे बुजुर्ग किसानों की जान चली गई, लेकिन तब भी खाद नहीं मिली। सरकार बताए कि खाद कहां है। अखिलेश यादव ने कहा कि जंगल से सटे जिलों में जंगली जानवर के हमलों में किसानों की जानें जा रही हैं। कहीं गुलदार हमले कर रहे है तो कहीं भेड़िया और बाघ के हमले हो रहे हैं। प्रदेश में न खाद है और न किसान सुरक्षित है।

सरकार ने सदन में भी झूठ बोला

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने जिन स्कूलों का मर्जर किया था, उन्हें फिर शुरू नहीं किया गया। सरकार ने सदन में भी झूठ बोला कि स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, ताकि लोग भरोसा कर लें। जिन लोगों ने पीडीए पाठशाला चलाई और जिन अभिभावकों ने उसमें अपने बच्चों को भेजा है, यह सरकार उनके खिलाफ भी मुकदमों की तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बूथ पर और ज्यादा काम करना होगा, ताकि कोई गड़बड़ न हो सके। मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मुद्दा उन्होंने फिर उठाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता चाहे किसी पर भी हमला करें या भ्रष्टाचार करें, उनके घरों पर बुल्डोजर नहीं चलेगा। यही भाजपा का चरित्र है। बदलाव के लिए जनता भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही है।

डॉ. शकुंतला विवि के दिव्यांगजनों ने अखिलेश को दिया ज्ञापन

पूर्व सीएम अखिलेश यादव को प्रदेश भर से आए दिव्यांगजनों ने ज्ञापन सौंपा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए जो योजनाएं चल रही थीं, उन्हें ठीक ढंग से लागू नहीं किया। सपा सरकार बनने पर दिव्यांगों को उनका हक और आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांग आयोग का गठन होगा। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर दिव्यांग छात्रों के शोषण के संबंध में भी ज्ञापन दिया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे।

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे सपा प्रमुख

अखिलेश यादव से यह पूछे जाने पर कि क्या वे राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा है। इसमें इस माह के अंतिम सप्ताह में शामिल होंगे।

नए विधेयक क्षेत्रीय दलों के खिलाफ षड्यंत्र

संसद में लाए गए नए विधेयक को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह विधेयक क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने और उन्हें तो?ने के षड्यंत्र के तहत लाया गया है। भाजपा सरकार झूठे और फर्जी मुकदमे लगाकर नेताओं को जेल भेजना चाहती है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं मो. आजम खां , विधायक रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया है।

पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही यूपी सरकार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही है। पूजा पाल को बताना चाहिए कि उन्हें किससे जान का खतरा है? अभी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव उन आरोपों पर बयान दे रहे थे जिसमें विधायक पूजा पाल ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सपा और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग फ्रस्टेट हो गए हैं इसीलिए अमर्यादित हरकतें कर रहे हैं। अभी बलिया में बिजली विभाग के कार्यालय में घुसकर एक दलित समाज से आने वाले इंजीनियर को जूतों से पीटा। उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय बाद इनके नेताओं के हाथों में जूता ही नजर आएगा।

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने गृहमंत्री को लिखा पत्र

सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक पूजा पाल के जान का खतरा होने के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि मामले की पूरी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सपा ने पूजा पाल का मुश्किल समय में साथ दिया था। ऐसे में उन्हें किससे जान का खतरा है इसकी जांच करवाई जाए।

किसानों को खाद के बदले मिल रहीं लाठियां : अवधेश प्रसाद

भाजपा सरकार में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। जो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा कर रही थी, उसी के राज में किसानों पर खाद के बदले लाठियां बरसाई जा रही हैं। यह बातें रविवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में सांसद अवधेश प्रसाद ने कहीं। उन्होंने कहा कि एक ओर छुट्टा पशु किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं तो दूसरी ओर उन्हें समय से खाद नहीं मिल पा रही है। यही यूरिया भाजपा से जुड़े लोगों के ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लादकर बाहर भेज दी जा रही है। खाद की कालाबाजारी में भाजपा कार्यकर्ता सीधे तौर पर शामिल हैं। जबकि, मेहनतकश किसान खाद की एक बोरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। यदि किसानों को समय पर खाद और सुरक्षा नहीं मिली तो आने वाले दिनों में भाजपा को गंभीर जनविरोध का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, महानगर अध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता लवलेश पांडेय, छोटेलाल यादव, राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप आदि मौजूद रहे।

वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई: भूपेंद्र सिंह हुड्डा

» सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों का चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। विधानसभा सत्र से पहले हरियाणा कांग्रेस वोट चोरी आरोप के मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस विधायकों ने आज कोर्ट चौक तक पैदल मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक इस विरोध मार्च में शामिल हुए।

कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई है और इसी कारण पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हारने वाले 16 प्रत्याशियों ने ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिन पर हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई थीं। इस बार भी कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रही है। बीते शुक्रवार को भी विधानसभा में कांग्रेस ने तीन घंटे तक कानून व्यवस्था और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा किया था। वहीं, राहुल गांधी ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर वोट चोरी और गड़बड़ी के मुद्दे को उठाते हुए हरियाणा का जिक्र किया था। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा की 8 सीटों पर बेहद कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी 23 हजार से भी कम वोटों के अंतर से हारे थे।

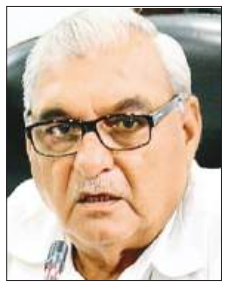

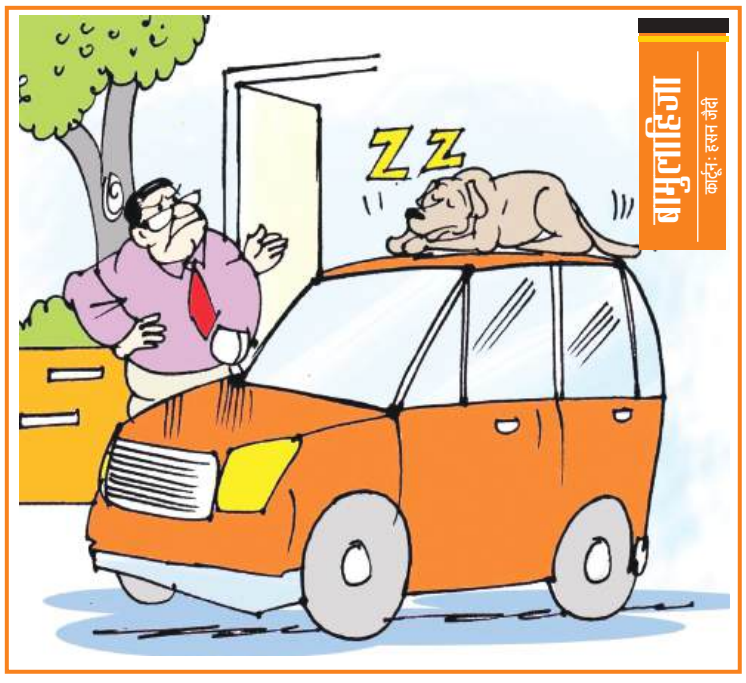

फिर वापसी के लिए ताकत लगाएगी बसपा

» नौ अक्टूबर को प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करेगी पार्टी

» कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर हो सकती है बड़ी रैली

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा पूरी ताकत से वापसी करने की रणनीति पर काम करने लगी है। आगामी 9 अक्तूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा कर पार्टी अपने बढ़ते जनाधार का प्रदर्शन करेगी। खासकर राजधानी में 9 अक्तूबर को विशाल रैली के आयोजन पर मंथन किया जा रहा है।

बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते दिनों कई कमेटियों का गठन किया था, जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बसपा के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं दूसरी ओर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी लगातार कैडर कैंप का आयोजन करने के साथ अन्य दलों के नेताओं को बसपा में शामिल करने की मुहिम में जुटे हैं। दरअसल, पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी कील-कांटे मजबूत कर लेना चाहती है।

अभी तक इंडिया गठबंधन या किसी भी अन्य दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले पर अडिग बसपा अपने दम पर दोबारा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मुफीद अवसर माना जा रहा है, जिसमें बसपा सुप्रीमो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में जानकारी देने के साथ उन्हें विपक्ष के झूठे प्रचार से भी अवगत कराएंगी। इस बाबत जल्द ही पार्टी के बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

जनता के संदेह को दूर करे भजन सरकार : गहलोत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार से पचपदरा-बालोतरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट की घोषणा संख्या 158 में अगस्त 2025 से रिफाइनरी में उत्पादन शुरू करने की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिफाइनरी का दौरा तो किया लेकिन अपने बयानों और सरकारी प्रेस नोट में उत्पादन शुरू होने की तारीख का जिक्र नहीं किया। गहलोत ने इसे आश्चर्यजनक चुप्पी बताते हुए कहा कि इससे जनता के बीच संदेह पैदा हो रहा है। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोविड जैसी चुनौती के बावजूद रिफाइनरी के 80त्न से अधिक काम पूरे कर लिए गए थे लेकिन 2013 से 2018 और अब 2023 से भाजपा सरकार की लेटलतीफी के कारण इस 37,000 करोड़ रुपये की परियोजना की लागत बढ़कर लगभग एक लाख करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने याद दिलाया कि 2013 में शिलान्यास के बाद अगर काम नहीं रोका गया होता तो लागत इतनी नहीं बढ़ती।

बंगाल में अभी से लगा चुनावी चौपाल

टीएमसी व भाजपा जनता के बीच पहुंची

» ममता व मोदी में दौरों की होड़

» कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरेंगी दीदी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। बिहार चुनाव के बाद दूसरे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य बंगाल में अगले वर्ष विधान सभा चुनाव होने हैं। बंगाल में सियासी दलों की पैंतरेबाजी भी चालू हो गइ है। जहां वहां की सीएम व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र के पीएम व सीएम हटाने वाले संविधान संशोधन बिल को सुपर आपातकाल बताकर उसका विरोध किया वहीं इस पर बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी-जेपीसी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। बता दें ममता बनर्जी ने की संविधान संशोधन विधेयक की निंदा, मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसे 'सुपर-आपातकाल' से भी बड़ा कदम बताया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक भारत के लोकतांत्रिक युग को समाप्त कर देगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा में बुधवार को 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025', 'संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' पेश किए। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में 30 दिन तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने का प्रावधान है।

दमनकारी कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मृत्यु संकेत है : ममता

ममता बनर्जी ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा आज लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि एक सुपर आपातकाल से भी बड़े, भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर मैं इसकी निंदी करती हूं। यह दमनकारी कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मृत्यु संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए।

कांग्रेस को पैनल में 4-5 सीटें मिलने की उम्मीद

कांग्रेस को पैनल में 4-5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके और समाजवादी पार्टी ने भी जेपीसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि, अब कांग्रेस को सहयोगी टीएमसी के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए गए तीन विधेयकों पर तीखी बहस हुई।अब क्या करेगी टीएमसी...इस बैठक में एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा कि विपक्ष को जेपीसी से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक छोटे दल के सदस्य ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि

जेपीसी ही एकमात्र ऐसा मंच है जहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है और असहमति भी दर्ज करा सकता है। टीएमसी सदस्य ने कहा कि सरकार अंततः अपना काम कर लेती है, जैसे कि वक्फ विधेयक पर जेपीसी में हुआ था। हालांकि, जवाब में यह बताया गया कि जेपीसी की कार्यवाही ने एक बड़ा उद्देश्य पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उनका उल्लेख किया था। फिलहाल विपक्ष हाल ही संपन्न हुए मॉनसून सत्र में एकजुट रहने में कामयाब रहा। लेकिन सत्र के अंतिम दिन पेश किए गए तीन विधेयकों ने कुछ दरारें पैदा कर दीं। अब देखना होगा कि टीएमसी क्या अपने रुख में कोई बदलाव करेगी। क्या टीएमसी जेपीसी का बहिष्कार जारी रखेगी? या फिर वह बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस समिति में शामिल होगी?

मोदी ने शुरू किये बंगाल के दौरे

देश में सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। करीब चार दशक बाद अब 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को नई रफ्तार दिया। पीए मोदी बिहार में परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद बंगाल पहुंचें। कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए रेल मंत्री ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया।

बंगाल की सीएम का ये भी दावा

ममता ने दावा किया कि यह विधेयक केंद्र सरकार को जनादेश में दखलंदाजी करने के लिए शक्ति देता है, तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जैसे गैर-निर्वाचित प्राधिकारियों को निर्वाचित राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों की कीमत पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को भयावह तरीके से सशक्त बनाने का कदम है। ममता ने कहा कि लोग अपनी अदालतों, अपने अधिकारों और अपने लोकतंत्र को छीनने के किसी भी प्रयास को माफ नहीं करेंगे।

केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप

ममता ने आरोप लगाया कि इस विधेयक का उद्देश्य %एक व्यक्ति-एक पार्टी-एक सरकार की प्रणाली को मजबूत करना है। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदता है। अब यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहता है। हम जो देख रहे हैं वह अभूतपूर्व है - यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर हिटलरी हमले से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए! इस समय लोकतंत्र को बचाना होगा!

जेपीसी से दूरी बनाएगी टीएमसी

केंद्र सरकार हाल ही संपन्न हुए संसद के मॉनसून सत्र में एक नया बिल लेकर आई। पीएम-सीएम को बर्खास्त करने वाले इस विधेयक को जैसे ही लोकसभा में पेश किया गया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने के प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने स्वीकृति दे दी। अब इस बिल के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाई जाएगी। जेपीसी में सभी दलों के सांसद होंगे। वे कानून पर विचार करेंगे और अपनी राय देंगे। भले ही ये विधेयक जेपीसी में चला गया हो लेकिन विपक्षी खेमे में इस बिल को लेकर घमासान जारी है।दरअसल, इस कानून के तहत अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए जेल हो जाती है, तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कई दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस कानून पर संसद में चर्चा हो। हालांकि, इस कानून को लेकर विपक्ष में मतभेद हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अलग रुख अख्तियार किया है।तृणमूल कांग्रेस इस ज्वाइंट पर्लियामेंट्री कमिटी में शामिल नहीं होना चाहती है। टीएमसी का कहना है कि इस कानून का विरोध करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, टीएमसी चाहती है कि जेपीसी का बहिष्कार किया जाए। लेकिन बाकी विपक्षी दल चाहते हैं कि वे पैनल में रहें। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार को विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाने का हथियार न मिले।

कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा व टीएमसी में रार

बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बवाल मचा रहता है। बीजेपी टीएमसी पर हमला करने का कोई भी मौका गंवाना नही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर ''राज्य पुलिस की मौजूदगी में'' हुए हमले के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बृहस्पतिवार को आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह घटना राज्य में उनकी सरकार में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने को दर्शाती है। नड्डा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''अराजकता और राजनीतिक हिंसा की इस संस्कृति को बढ़ावा देने'' के लिए ममता बनर्जी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर

निकाली गई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रैली पर कुछ लोगों ने बुधवार को कथित रूप से पथराव किया और काले झंडे दिखाए। भाजपा ने इस घटना के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। नड्डा ने कहा, ''मैं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कूचबिहार में तृणमूल के गुंडों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि यह हमला राज्य पुलिस की मौजूदगी में हुआ जो ममता बनर्जी की सरकार में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर भी हमला है। नड्डा ने कहा कि उन्होंने अधिकारी से बात की और स्थिति का जायजा लिया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की दुर्दशा की केवल कल्पना ही की जा सकती है। हालांकि इस मामले टीएमी कह चूकी है कि भाजपा अपने शासित राज्यों के के बारे में भी बात जरूर करे। जहां की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

पर्यावरण व प्रकृति पर अत्याचार रोकने पड़ेंगे!

पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने केवल वर्षा के स्वरूप को बदल दिया है, बल्कि यह भी देखा गया है कि अब वर्षा कम समय में अधिक मात्रा में होती है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और ढलानों से मलबा फिसलने लगता है। हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

उत्तराखंड में फिर बादल फटने से तबाही आ गई है। महीने भर के भीतर इस तरह की आपदा दूसरी बार आयी है। पहले जहां धराली में भयनक मंजर था अब थराली में ऐसा नजारा देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना पर्यावरण में बदलाव की वजह से ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इनकों रोकने के लिए हमें पर्यावरण व प्रकृति पर अत्याचार रोकने पड़ेंगे अन्यथा इस तरह की तबाही से बच पाना आसान नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने केवल वर्षा के स्वरूप को बदल दिया है, बल्कि यह भी देखा गया है कि अब वर्षा कम समय में अधिक मात्रा में होती है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और ढलानों से मलबा फिसलने लगता है। हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्डतोड़ बारिश ने कई स्थानों पर बड़े भूस्खलनों को जन्म दिया, जिससे सैकड़ों घर और सड़कें बर्बाद हो गईं। केरल और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में भी भारी वर्षा के बाद भूस्खलन आम हो गया है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में सतही तापमान में वृद्धि से बर्फ तेजी से पिघल रही है और उसकी वजह से नीचे की चट्टानों की स्थिरता प्रभावित हो रही है।

इसके साथ-साथ मानवीय गतिविधियां जैसे अवैज्ञानिक निर्माण, पेड़ों की कटाई और अवैध खनन भी इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल औसतन 300 से अधिक भूस्खलन दर्ज किए जाते हैं। इनमें से कई जानलेवा साबित होते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय मौसम विभाग ने भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, लेकिन इनका विस्तार सीमित क्षेत्रों तक ही है। भारत में विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी मानसूनी वर्षा और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण भूस्खलन आम बात हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण, सड? चौड़ीकरण, वनों की कटाई और बढ़ती आबादी के कारण ढलानों की स्थिरता लगातार कमजोर हो रही है। 2023 में केवल हिमाचल प्रदेश में 80 से अधिक बड़े भूस्खलन दर्ज किए गए, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ। भारत में जलवायु परिवर्तन मानसून के स्वरूप को असामान्य बना रहा है, जिससे कम समय में तीव्र वर्षा होती है और पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगती है।भारत में राज्य आपदा प्राधिकरण सक्रिय तो हैं, लेकिन संसाधनों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित पहुंच और प्रशासनिक ढिलाई के चलते समय पर चेतावनी और राहत देना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

मानसून के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत

श्रवण प्रभु

दक्षिण-पश्चिम मानसून को भारत की जल और खाद्य तंत्र की रीढ़ कहा जाता है, जो जून से सितंबर के बीच देश में लगभग तीन-चौथाई वार्षिक वर्षा लाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। लेकिन इसमें सिर्फ यही मायने नहीं रखता है कि कुल कितनी बारिश हुई, बल्कि यह भी अहम है कि कब, कहां और कैसी बारिश हुई है। जलवायु परिवर्तन ने बारिश के पैटर्न को अनियमित बनाया है। वर्ष 2025 में अब तक का मानसून पूरे देश में भारी और कम वर्षा की विरोधी घटनाओं से भरा हुआ है। जुलाई में अच्छी बारिश ने खरीफ की बुवाई को तेज कर दिया, माह के अंत तक 70.8 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुवाई हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 4.1 प्रतिशत अधिक रही।

दूसरी तरफ केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों को अत्यधिक बारिश से जूझना पड़ा है, जिससे अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं। सीईईडब्ल्यू के एक अध्ययन में पाया गया कि 55 प्रतिशत तहसीलों में जून से सितंबर के बीच कुल बारिश बढ़ी है। खास बात यह कि यह बढ़ोतरी भारी बारिश वाले दिनों की संख्या बढ़ने से हुई है। नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पिछले चार दशकों में प्रति घंटे बारिश के पैटर्न की पड़ताल में सामने आया है कि मध्य भारत में कम समय में भारी बारिश और उत्तर-पश्चिमी तट पर लंबे समय तक भारी बारिश की घटनाएं अधिक संख्या में हो रही हैं। पिछले दो दशकों में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में उल्लेखनीय रूप से निवेश किया है और देश व राज्यों के स्तर पर जलवायु कार्य योजनाएं शुरू की हैं। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, और बारिश में तेजी से अनियमितता आ रही है, इसका सामना करने की क्षमता विकसित करने में ये तीन कदम सहायक हो सकते हैं। पहला, शहरों को बीते कल के औसत के लिए नहीं, बल्कि आज के तूफानों के लिए योजना बनानी चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को बाढ़ का सामना करने के लिए बनाई जाने वाली योजना का दोबारा मूल्यांकन करना चाहिए।

पारंपरिक बाढ़ प्रबंधन इस ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है कि कितनी बार और कितनी भारी बारिश हुई है, जिसे तूफानी घटनाओं की तीव्रता-अवधि-आवृत्ति कहा जाता है।

लेकिन अब यह विश्वसनीय नहीं रह गया है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका मतलब लंबे समय तक सूखा पड़ना और फिर बहुत तेज बारिश होना है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुराने जल-निकासी तंत्र (ड्रेनेज सिस्टम) को एक घंटे की अधिकतम बारिश को संभालने के लिए नहीं बनाया गया था, जबकि बीते एक दशक में औसतन बारिश 64 मिमी प्रति घंटा रही है। (संदर्भ के लिए, 100 मिमी प्रति घंटा बारिश को बादल फटना माना जाता है।) इसे समझते हुए, ठाणे नगर निगम ने अपने बाढ़ के खतरे के अनुमानों में बदलाव किया है और अब अपने तूफानी जल-निकासी वाले नालों (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स) को फिर से बना रहा है। भारत के अन्य शहरों को भी ऐसा करना चाहिए। दूसरा, किसानों को अपने फसल कैलेंडर को अपडेट करने की जरूरत है। बारिश के बदलते पैटर्न के साथ, राज्यों और केंद्रीय कृषि विभागों और मौसम विज्ञान एजेंसियों को मिलकर फसल कैलेंडर को अपडेट करना चाहिए, खास तौर पर जिन क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती होती है। अध्ययन से पता चलता है कि अनिश्चित मानसूनी बारिश विशेष रूप से धान, मक्का और दालों जैसी प्रमुख फसलों के बुवाई और कटाई के मौसम को बदल रही है। वहीं, भारत की आधी से अधिक तहसीलों में अक्टूबर महीने में बारिश में वृद्धि देखी गई, जिससे फसलों की कटाई प्रभावित होती है। परंपरागत रूप से फसल का नुकसान होने पर राहत भुगतान की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक अधिक दूरदर्शी दृष्टिकोण में फसल चक्रों को नए सिरे से व्यवस्थित करना, जलवायु-अनुकूल बीज उपलब्ध कराना, और किसानों की सुरक्षा के लिए आकस्मिक योजनाओं का निर्माण शामिल होना चाहिए।

तीन, स्थानीय स्तर पर मौसम के अधिक सूक्ष्म आंकड़ों को जुटाने में निवेश करें और उनके उपयोग की क्षमता बढ़ाएं। स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रतिक्रिया देने और इन पूर्वानुमानों और अधिक उन्नत बनाने के साथ मानसून पूर्व-आकलनों को दूरदर्शी बनाने के लिए हमें और अधिक सूक्ष्म या बारीक आंकड़ों की जरूरत है। डॉपलर रडार और स्वचालित मौसम स्टेशनों के नेटवर्क में विस्तार, जैसा कि मिशन मौसम के तहत परिकल्पित है, स्थानीय पूर्वानुमानों में सुधार ला सकता है। आईएमडी का भारत फोरकास्टिंग सिस्टम एक सही कदम है।

कसौटी पर हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देश

के.पी. सिंह

दिल्ली के बाद, हरियाणा सरकार ने भी 16 अगस्त, 2025 को सामुदायिक सेवा दिशा-निर्देश (एचसीएसजी) अधिसूचित कर दिए हैं। दोनों ही दिशा-निर्देशों के आरम्भिक वाक्य में कहा गया है कि ये दिशा-निर्देश भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 4 (एफ) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत बनाए गए हैं, जबकि इनमें से कोई भी प्रावधान राज्य सरकार को ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 (एफ) अपराधियों को दी जाने वाली सजा के प्रकार उल्लिखित करती है, तथा संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यकारी शक्तियों की सीमा का प्रावधान है। किसी भी विषय पर नियम अथवा दिशा-निर्देश जारी करने की शक्तियां सम्बन्धित कानून में स्पष्ट रूप से लिखित प्रावधान द्वारा कार्यपालिका को प्रदान की जाती हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) दोनों ही केन्द्रीय कानून हैं और राज्य सरकारें सामुदायिक सेवा दंड (सीएसएस) के निष्पादन पर प्रत्यायोजित (डेलिगेटिड) कानून का सहारा उसी परिस्थिति में ले सकती हैं जब इन कानूनों में इसका स्पष्ट प्रावधान हो। हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देशों को जायज ठहराने के लिए राज्यों को इससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाला कोई प्रावधान नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया बिना कानूनी आधार की गतिविधि मात्र बनकर रह जाती है। वास्तव में, बीएनएसएस का मसौदा तैयार करते समय विधान मंडल अनभिज्ञता से अध्याय 34 में सीएसएस के निष्पादन से सम्बन्धित उचित प्रावधान जोड़ना भूल गए, जैसा कि पहले से ही मृत्यु दंड, कारावास अथवा जुर्माना लगाने की सजा के निष्पादन के लिए किया गया है। यह त्रुटि शायद लापरवाही के कारण हुई क्योंकि सामुदायिक सेवा को बीएनएस में पहली बार दंड की सूची में शामिल किया गया था। परिणामस्वरूप, सीएसएस के निष्पादन पर नियम बनाने की शक्ति भी गैर-निर्देशित रह गई।

आदर्श रूप से, हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देश तैयार करने से पूर्व, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के समक्ष बीएनएसएस में वर्णित धारा 460 के बाद एक नए उप-शीर्षक 'सामुदायिक सेवा' के अन्तर्गत एक नई धारा शामिल करने का प्रस्ताव भेजना चाहिए था। ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों के अभाव में, हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देश और दिल्ली के दिशा-निर्देश, राज्य-कार्यपालिका की विधायी अक्षमता का शिकार हैं और दोनों ही दस्तावेज गैर-कानूनी हैं। यह आश्चर्यजनक है कि इतनी बड़ी गलती कैसे उजागर नहीं हो सकी। हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देश कई अन्य प्रकार से भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। सबसे पहले, दिशा-निर्देश यह वर्णित करते हैं कि वे उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां बाल-न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 18(1) (सी) के अन्तर्गत बच्चों को सामुदायिक सेवा करने के आदेश पारित किए जाते हैं। चूंकि बाल-अधिनियम महिला और बाल विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए यह उचित नहीं है कि गृह विभाग इसके कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश जारी करे।

दूसरा, उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 7 में अदालतों के लिए एक सुझाव दिया गया है कि सीएसएस आमतौर पर पहली बार अपराध करने वालों को दिया जाना चाहिए, जबकि बीएनएस में, छोटी-मोटी चोरी के मामलों को छोड़कर, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। इससे यह प्रासांगिक प्रश्न भी उठता है कि 'क्या कार्यपालिका दिशा-निर्देशों में ऐसी कोई अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकती है जो मूल अधिनियम में नहीं हैं'? अथवा 'क्या कार्यपालिका को यह निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि अदालतों को अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए?' तीसरा, वयस्क अपराधियों और बाल अपराधियों के लिए सीएसएस पर दिशा-निर्देशों को एक ही दस्तावेज में शामिल करना नीति संगत प्रतीत नहीं होता है। किशोरों के लिए सामुदायिक कार्य पर दिशा-निर्देशों को बच्चों और किशोरों से सम्बन्धित श्रम कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। चौथा, सीएसएस एक सजा है जो न केवल दोषी के पिछले चारित्रिक रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, बल्कि उसके खिलाफ भविष्य में होने वाली किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर भी असर रखती है। इसलिए, दिशा-निर्देशों में सामुदायिक सजा के निष्पादन के उचित दस्तावेजीकरण की एक योजना निर्धारित की जानी चाहिए थी। पांचवां, उपरोक्त दिशा-निर्देश आपराधिक न्याय-शास्त्र के इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त की अनदेखी करते हैं कि सजा देना अदालतों का विशेषाधिकार है, जबकि राज्य को यह निर्धारित करना होता है कि सजा का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। कार्यपालिका को ऐसे निर्देश देने से बचना चाहिए। ऐसे निर्देश केवल 'उच्च न्यायालय के नियम और आदेश' के अन्तर्गत ही जारी किए जा सकते हैं। छठा, दिशा-निर्देशों में 'नामित अधिकारी', 'नोडल अधिकारी' और 'सक्षम प्राधिकारी' आदि जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया हैं, जो भारत में सुधारात्मक न्याय-शास्त्र के लिए नई है। चूंकि सामुदायिक सेवा एक मूलभूत सजा है, इसलिए इसके निष्पादन के सन्दर्भ में प्रयुक्त शब्दावली अन्य दंडों के समान ही होनी चाहिए। राज्य को जेल अधीक्षक के अधीन एक सामुदायिक सेवा अधिकारी को नियुक्त करके सामुदायिक सेवा की सजा की निगरानी, पर्यवेक्षण और उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

बप्पा को लगाएं चॉकलेट मोदक का भोग

सावन के बाद से भारत में त्योहारों की झड़ी लग जाती है। रक्षाबंधन के कुछ दिन बाद ही गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन से गणेश उत्सव का आरंभ होता है, जोकि पूरे 10 दिन तक चलता है। गणेश उत्सव की धूम हर जगह दिखाई देती है। दस दिन तक लोग घरों में बप्पा को स्थापित करके रखते हैं। इन दस दिनों में उन्हें खूब पकवानों का भोग लगाया जाता है। अगर गणपति बप्पा के प्रिय भोग की बात करें तो इसमें मोदक सबसे पहले आता है। वैसे तो बाजार में आपको हर तरह के मोदक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से मोदक बनाकर इसका भोग भगवान गणेश को लगाएंगे तो इससे बप्पा जरूर प्रसन्न होंगे। इस बार गणपति उत्सव में आप बप्पा को साधारण की जगह चॉकलेट मोदक का भोग लगा सकते हैं।

सामान

मिल्क चॉकलेट-200 ग्राम, कोको पाउडर-1 बड़ा चम्मच, स्टफिंग के लिए सामान, खोया (मावा)-100 ग्राम, चीनी पाउडर- 2 बड़े चम्मच, नारियल बूरा- 2 बड़े चम्मच, काजू, बादाम, पिस्ता (बारीक कटे हुए), इलायची पाउडर, घी।

विधि

चॉकलेट मोदक बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। स्टफिंग को तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में मावा को हल्की आंच पर भून लें। इसे तब तक भूनें जब तक यह हल्का गुलाबी न हो जाए और घी छोड़ने लगे। जब मावा घी छोड़ने लगे तो इसमें चीनी पाउडर, नारियल बूरा, काजू, बादाम, पिस्ता, और इलायची पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और फिर आंच से उतारकर ठंडा होने दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक मिल्क चॉकलेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे माइक्रोवेव में पिघला लें। इस पिघली हुई चॉकलेट में कोको पाउडर मिलाएं ताकि एकसार मिश्रण बन जाए। अब मोदक बनाने की विधि शुरू करनी है तो सबसे पहले मोदक मोल्ड को हल्का घी से चिकना करें। अब इस मोल्ड के अंदर तैयार की गई स्टफिंग भरें। अच्छी तरह से स्टफिंग भरने के बाद इसे निकाल लें। इसी तरह से मोदक तैयार करें। सभी मोदक तैयार होने के बाद इसके ऊपर पिघली हुई चॉकलेट डालें। इसे फिर से 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें ताकि यह पूरी तरह से सेट हो जाए। आपके स्टफिंग वाले चॉकलेट मोदक तैयार हैं। इसका भोग लगाने के बाद आप इसे प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं।

बच्चे को भी पिलाएं ये स्वादिष्ट जूस

आजकल की बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना काफी मुश्किल हो जाता है। दरअसल, लोग नौकरी और पढ़ाई की आपाधापी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने का समय ही नहीं मिल पाता। यदि आप भी उन्हीं लोगों में हैं, जिनके पास सेहत का ध्यान रखने का समय नहीं है तो यहां हम आपको एक ऐसी जूस की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो सेहत के लिए काफी लाभदायक है। हम यहां बात कर रहे हैं चुकंदर के जूस की, जिसको पीने से शरीर की कई परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुकंदर में कई अनगिनत पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप घर पर कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट पेय पदार्थ बनाना चाहते हैं तो चुकंदर का जूस बनाकर खुद भी सकते हैं और अपने परिवारवालों को भी पिला सकते हैं।

सामान

2-3 मध्यम आकार के चुकंदर, 1 गाजर, 1 सेब, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा नींबू का रस, स्वाद के लिए नमक, पानी।

विधि

चुकंदर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर, गाजर और सेब को धोकर छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आप अदरक का उपयोग कर रहे हैं तो उसे भी छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अदरक का इस्तेमाल पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अब जूसर में कटे हुए चुकंदर, गाजर, सेब और अदरक डालें। यदि आप चाहें तो थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं ताकि जूस थोड़ा पतला हो सके। वरना बिना पानी के भी जूस तैयार कर सकते हैं। अब जूसर को चालू करें और सभी सामग्री का रस निकालें। इसे निकालकर छलनी की मदद से छान लें। ताकि बीच-बीच में किसी भी चीज के तिनके स्वाद को खराब न करें। अब जब जूस तैयार हो जाए, तो उसमें आधा नींबू का रस मिलाएं। नींबू के रस के अलावा इस जूस में स्वादानुसार थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं। बस आपका ये स्वादिष्ट और पौष्टिक जूस तैयार है।

हंसना मना है

टीचर: 'हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा' का मतलब बताओ? बच्चा: जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है, उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है?

टीचर- इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके बताओ- मुंह में पानी आना, छात्र- जैसे ही मैंने नल की टोंटी से मुंह लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया, टीचर- गेट आउट।

अध्यापक संता से- ताजमहल किसने बनाया? संता - जी, कारीगर ने! अध्यापक- मेरा मतलब है कि बनवाया किसने था? संता-जी, ठेकेदार ने, अध्यापक बेहोश।

अंकल बबलू से- तू स्कूल क्यों नहीं जाता, बबलू- कई बार गया अंकल पर वो वापिस भगा देते है, अंकल -क्यों? बबलू- कहते हैं भाग तेरा क्या काम लड़कियों के स्कूल में।

कहानी | पांच मिनट का जीवन

एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गये वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा, बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आये हैं लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह, वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा वत्स तुम्हारा पांच मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था।

शिक्षा - यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचे, और न ही बुरा करें। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

मेहनत का फल मिलेगा। सामाजिक कार्य करने में रुचि रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। कारोबार मनोनुकूल लाभ देगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से परिचय बढ़ेगा।

वृषभ

दूर से सुखद सूचना मिल सकती है। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। बुद्धि का प्रयोग करें।

मिथुन

नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति पर व्यय होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा।

कर्क

पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएं।

सिंह

परिवार तथा मित्रों के साथ कोई मनोरंजक यात्रा का आयोजन हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने का योग है। मित्रों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे। समय अनुकूल है।

कन्या

कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। योजना फलीभूत होगी। कारोबार में वृद्धि पर विचार हो सकता है। नौकरी में अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे। मातहतों का सहयोग मिलेगा।

तुला

किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की आयोजना हो सकती है। सत्संग का लाभ मिलेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। घर-बाहर सुख-शांति रहेगी। धन प्राप्ति में बाधाएं दूर होंगी।

वृश्चिक

चोट व दुर्घटना से हानि संभव है। लापरवाही न करें। किसी व्यक्ति से व्यर्थ विवाद हो सकता है। मानसिक क्लेश होगा। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

धनु

जल्दबाजी से काम बिगड़ेंगे तथा समस्या बढ़ सकती है। विरोध होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। बाहर जाने की योजना बनेगी। नौकरी में चैन रहेगा।

मकर

भूमि, भवन, दुकान, शोरूम व फैक्टरी इत्यादि की खरीद-फरोख्त हो सकती है। बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे।

कुम्भ

कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। कोई मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

मीन

दूसरे से अधिक अपेक्षा करेंगे। जल्दबाजी से काम में बाधा उत्पन्न होगी। दौड़धूप अधिक रहेगी। बुरी सूचना मिल सकती है, धैर्य रखें। बनते कामों में देरी होगी।

बॉलीवुड | मन की बात

मेरे गले व होठ सूख गये बताते बताते कि मैं जिंदा हूं : रजा मुराद

रजा मुराद हाल ही में एक परेशान करने वाले मामले का शिकार हुए। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी खबर फैल गई, जिसके बाद अभिनेता को न सिर्फ मानसिक तनाव झेलना पड़ा बल्कि मजबूर होकर उन्होंने मुंबई के अंबोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अपने करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके एक्टर रजा मुराद ने बताया कि उनकी मौत की अफवाह इतनी तेजी से फैली कि उन्हें देश-विदेश से लगातार फोन और संदेश आने लगे। किसी ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की तारीख, जन्मतिथि और यहां तक कि श्रद्धांजलि संदेश तक लिख दिया। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर अभिनेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। अभिनेता ने बताया कि बार-बार यह सफाई देना कि वे जिंदा हैं, उनके लिए बेहद थका देने वाला रहा। उन्होंने कहा कि उनके गले और होंठ सूख गए हैं यह बताते-बताते कि वे जीवित हैं। लोगों की ओर से लगातार शोक संदेश और संवेदनाएं मिलने लगीं, जिसने उन्हें बेहद आहत किया। इस घटना को उन्होंने शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसे लोग बेहद छोटे स्तर की मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। यही वजह है कि वो दूसरों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें करके संतोष पाते हैं। रजा मुराद ने बताया कि पुलिस ने उनकी शिकायत गंभीरता से ली है और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस साजिश के पीछे जो भी शख्स होगा, उसे जल्द पकड़ा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिनेता ने यह भी कहा कि मशहूर हस्तियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब वे जीवित रहते हैं, तब भी उन्हें सोशल मीडिया पर मृत घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की फेक न्यूज पर अंकुश लगाना जरूरी है और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रजा मुराद का करियर रजा मुराद ने 1970 के दशक से लेकर आज तक हिंदी, भोजपुरी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया है।

फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग शुरू

सलमान खान इस वक्त लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ सलमान के बिग बॉस 19 का आगाज होने जा रहा है, दूसरी तरफ उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग शुरू हो गई है। इस वीकेंड बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे फैन्स को सलमान की फिल्म के सेट से पहली झलक भी देखने को मिल गई है। फिल्म के सेट से नई तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ हो गया है कि सुपरस्टार ने लद्दाख में मच अवेटेड वॉर ड्रामा की शूटिंग शुरू कर दी है।

अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म एक बड़े पैमाने पर देशभक्ति की गाथा होने की उम्मीद है।

लद्दाख से सामने आई सलमान खान की पहली तस्वीर

यह खबर तब सामने आई जब सलमान की सेट पर लद्दाख की खूबसूरत बैकग्राउंड में एक तस्वीर ऑनलाइन शेयर की गई। यह तस्वीर तेज़ी से वायरल हो गई और फैन्स और फिल्म जगत के लोगों ने उन्हें फिल्म के लिए बधाई देना शुरू कर दिया।

लद्दाख में शूटिंग गलवान की लड़ाई के विशाल पैमाने को उजागर करती है। यह ऊंचाई वाला क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण स्थान है, जिससे पता चलता है कि फिल्म में दमदार एक्शन सीन्स होने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री के एनालिसट तरण आदर्श ने भी यह अपडेट शेयर करते हुए कहा कि सलमान खान की ज़बरदस्त मौजूदगी इस देशभक्ति की गाथा को एक नए लेवल पर ले जाएगी। सामने आई तस्वीर ने फैन्स को काफी एक्साइटेड कर दिया है। बैटल ऑफ़ गलवान जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई वॉर पर बेस्ड है। यह फिल्म देश की सीमा की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की कहानी बयां करेगी। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की दमदार भूमिका निभाएंगे, जो एक ऐसे कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्हें उनके असाधारण साहस के लिए मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

रागिनी एमएमएस- 3 में हुई तमन्ना भाटिया की एंट्री

एकता कपूर की हॉरर फ्रेंचाइची 'रागिनी एमएमएस' बहुत पॉपुलर है। अब तक इसके दो पार्ट बन चुके हैं। अब इस फ्रेंचाइजी में तमन्ना भाटिया की एंट्री हो गई है। 'रागिनी एमएमएस 3' में वह लीड रोल निभाएंगी। ऐसी खबरें हैं कि एकता कपूर इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनाना चाहती हैं। 'रागिनी एमएमएस 3' फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। पिंकविला को एक सोर्स ने बताया कि एकता कपूर काफी समय से 'रागिनी एमएमएस' का तीसरा पार्ट बनाना चाह रही थीं। कई आइडियाज पर मंथन करने के बाद उन्होंने आखिरकार एक ऐसे कॉन्सेप्ट को फाइनल किया है, जो न सिर्फ रागिनी एमएमएस यूनिवर्स में फिट बैठता है, बल्कि इसे एक बिल्कुल नए जॉनर में रीब्रांड भी करता है। यह फिल्म साल 2025 के आखिर तक फ्लोर पर जा सकती है। तमन्ना भाटिया को इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई है।

सोर्स ने यह भी बताया कि एकता कपूर ने 'वन' के सेट पर तमन्ना भाटिया को फिल्म की कहानी सुनाई थी और इसकी नई तरह की हॉरर थीम सुनकर एक्ट्रेस हैरान रह गईं। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्में हॉरर-इरोटिका पर ज्यादा आधारित थीं, वहीं 'रागिनी एमएमएस 3' अब हॉरर-कॉमेडी फॉर्मेट को एक्सप्लोर करेगी। टीम एक ऐसे धमाकेदार म्यूजिक नंबर की भी तलाश कर रही है, जिसमें चार्टबस्टर बनने की पूरी क्षमता हो। कुछ वैसा ही जैसा 'रागिनी एमएमएस 2' का आइकॉनिक गाना 'बेबी डॉल' था। साल 2011 में हुई फ्रेंचाइजी की शुरुआत 'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2011 में राजकुमार राव और कायनाज मोटवाला के साथ हुई थी, जिसके बाद 2014 में सनी लियोनी स्टारर 'रागिनी एमएमएस 2' आई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली, खासकर इसके हिट गाने 'बेबी डॉल' की वजह से, जिसने इसे पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। बताया जा रहा है कि एकता कपूर की 'रागिनी एमएमएस 3' में डर, कॉमेडी और म्यूजिक का जबरदस्त मेल दर्शकों को मिलेगा।

अजब-गजब | उदयपुर के चांदनी गांव का है अनसुलझा रहस्य!

शाम ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर शहर से महज 15 किलोमीटर दूर बसा चांदनी गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसके साथ जुड़ा एक ऐसा डरावना रहस्य है, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। दिन में यह गांव सैलानियों के लिए स्वर्ग सा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यहां की फिजाओं में एक अजीब सा सन्नाटा और दहशत छा जाती है। क्या है इस गांव का वो राज, जो इसे बनाता है राजस्थान का सबसे रहस्यमयी ठिकाना? आइए, जानते हैं इस गांव की डरावनी कहानी!

चांदनी गांव की खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। हरे-भरे पहाड़, बहती नदी, और ठंडी हवाओं का झोंका मानो प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। मानसून में तो यह गांव किसी जन्नत से कम नहीं है। सैलानी दूर-दूर से इसकी हरियाली और शांति का लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब होती है गांव की गलियों में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसर जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहां आत्माएं घूमती है।

ग्रामीणों का दावा है कि सूर्यास्त के बाद चांदनी गांव की गलियों और नदी किनारे अजीब-अजीब आकृतियां दिखाई देती है। कुछ लोगों ने तो इंसानी शक्ल वाले सायों को देखने की बात कही है, जो पास जाने पर हवा में गायब हो जाते

हैं। गांव के सुरेश मीणा बताते हैं कि एक बार रात में नदी किनारे एक औरत की परछाई देखी। वो मुझे पुकार रही थी, लेकिन जैसे ही मैं पास गया, वो गायब हो गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कई लोगों ने रात में चीखने और रोने की आवाजें सुनने की बात भी कही है, जो सुनने में किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है।

चांदनी गांव के लोग इस डर से इतने सहमे हुए हैं कि शाम 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आता है, तो उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि सूरज ढलने से पहले गांव छोड़ दे। गांव के बुजुर्ग रामलाल बताते हैं कि यह डर पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे दादा-परदादा भी यही कहते थे कि रात में गांव की गलियों में अकेले मत घूमना। इस डर की वजह से गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता है और हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं।

क्या वाकई चांदनी गांव में आत्माएं भटकती हैं, या ये सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जब पूरा गांव एक ही बात कहता है, तो कहीं न कहीं कोई सच्चाई तो छिपी हो सकती है। कुछ का कहना है कि गांव के पास की नदी में कई साल पहले कुछ दुखद घटनाएं हुई थी। जिनकी आत्माएं आज भी शांति की तलाश में भटक रही हैं। वहीं, कुछ इसे सैलानियों को आकर्षित करने की कहानी मानते हैं। लेकिन जो भी हो, इस रहस्य ने चांदनी गांव को एक अनोखा डरावना आकर्षण जरूर बना दिया है।

चांदनी गांव की यह रहस्यमयी कहानी इसे सैलानियों के लिए और भी आकर्षक बनाती है। जो लोग रोमांच और रहस्य के दीवाने हैं, उनके लिए यह गांव किसी खजाने से कम नहीं। दिन में इसकी प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाइए और अगर हिम्मत हो तो सूरज ढलने के बाद इसके रहस्यमयी सायों का पीछा कीजिए। चांदनी गांव की यह कहानी सच हो या झूठ, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह गांव अपने रहस्य और खूबसूरती के मेल से हर किसी को हैरान करता है। तो अगली बार उदयपुर जाएं, तो चांदनी गांव जरूर घूमें। लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएं, वरनाज कौन जाने, कोई भटकती आत्मा आपसे मुलाकात करने चली आए।

यूपी का है ये 800 साल पुराना सिंहासन इस पर जो भी बैठा उसकी हो गई मौत

कौशांबी। दुनिया भर में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग मनहूस या अशुभ मानते हैं। भले ही इनके पीछे वैज्ञानिक कारण न हों, लेकिन धार्मिक मान्यताओं, लोककथाओं और परंपराओं की वजह से इन पर विश्वास किया जाता है। भारत ही नहीं, बल्कि अलग-अलग देशों में भी ऐसी कई धारणाएं मौजूद हैं। इतिहास में कई ऐसे सामान का जिक्र हैं, जिन्हें राजपाट और सत्ता से जुड़ा होने के बावजूद अशुभ या मनहूस माना गया है। माना जाता है कि इन वस्तुओं के कारण कई राजवंश बर्बाद हुए और राजाओं की अकाल मृत्यु हुई। भारत में इसके कुछ उदाहरण मौजूद हैं जैसे कोहिनूर हीरा, नसीराबाद का ताज, दिल्ली का तख्त-ए-ताऊस, औरंगजेब की तलवार। ठीक ऐसी ही कहानी कालेश्वर घाट के इस तख्त की भी है। तख्त का नाम सुनते ही आमतौर पर सुकून और चैन का अहसास होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कड़ा धाम कालेश्वर घाट पर स्थित एक रहस्यमयी तख्त लोगों के लिए खौफ का कारण बनी हुई है। कहा जाता है कि हाथियों की हड्डियों से बना यह तख्त इतना मनहूस है कि जिस किसी ने भी इस पर बैठने की कोशिश की, या तो उसकी मौत हो गई या फिर वह मानसिक संतुलन खो बैठा। मौत की इन घटनाओं के चलते अब इस सेज के चारों ओर हमेशा पहरा रहता है और दो पहरेदार लगातार लोगों को इसे छूने से रोकते हैं।यह रहस्यमयी सेज कालेश्वर घाट पर गंगा किनारे स्थित है और इसका इतिहास करीब 800 साल पुराना बताया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बाबा उमरा के लिए यह विशेष सेज बनाई गई थी। लेकिन बाबा के जीवित समाधि लेने के बाद से यह तख्त सुनसान पड़ा है। पुजारी रोज़ाना उस कमरे की सफाई करते हैं, जहां यह तख्त रखा है। गांव के बुजुर्गों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस तख्त पर बैठने वाले कई लोग या तो असमय मौत के शिकार हुए या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। यही वजह है कि इसे अब मौत की सेज कहा जाने लगा है। इस जगह पर राम नाम के भजन और डोलक-मंजीरे की आवाज़ें गूंजती जरूर हैं, लेकिन यह किसी उत्सव या आराधना का प्रतीक नहीं बल्कि रहस्य से भरी एक दास्तान है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, उमरा बाबा अल्हा-उदल के गुरु थे और उन्होंने इसी परिसर में जीवित समाधि ली थी। पूरी तरह से हाथी की हड्डियों से बनी यह सेज आज भी शोध और रहस्य का विषय बनी हुई है। प्रशासन और विज्ञान अभी तक इसके पीछे के सच का खुलासा नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिलहाल यह जगह मौत की घटनाओं की वजह से सुरक्षा घेरे में है और लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है।

मप्र में कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर बवाल

दिग्विजय बोले - सिंधिया और कमलनाथ के बीच थी अनबन

» गलत आरोप मेरे सिर पर मढ़े गए : पूर्व सीएम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश में पांच साल पहले गिरी कांग्रेस सरकार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक पॉडकास्ट में कई खुलासे किए। दिग्विजय ने बताया कि सरकार आइडियोलॉजिकल क्लैश से नहीं बल्कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी से गिरी थी। दिग्विजय सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने एक उद्योगपति से मध्यस्थता करवाई थी, जिनके कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों से अच्छे संबंध थे। उनके घर पर डिनर के दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी और एक विशलिस्ट तैयार हुई।

इसमें ग्वालियर-चंबल संभाग से जुड़े फैसलों पर साथ मिलकर काम करने का आश्वासन भी शामिल था। दिग्विजय के बताया कि उन्होंने भी लिस्ट पर दस्तखत किए थे, लेकिन बाद में उसका पालन नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि जिन पर पूरा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने धोखा दिया। अगर ग्वालियर-चंबल से जुड़ी मांगें मानी जातीं तो शायद सरकार गिरने की नौबत नहीं आती। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रचारित किया गया कि उनकी और सिंधिया की लड़ाई से सरकार गिरी, जबकि हकीकत यह नहीं है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझ पर हमेशा वही आरोप लगाए जाते हैं, जिनका मैं दोषी नहीं होता हूं।

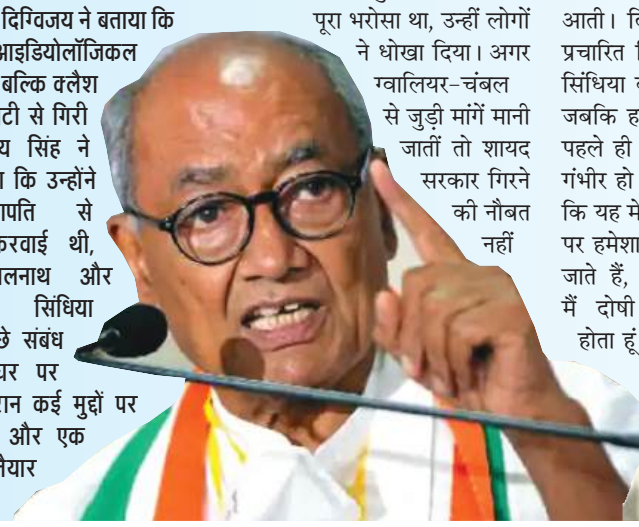

राहुल ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों को दी ट्रेनिंग

प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त 71 शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को दिल्ली में पहली ट्रेनिंग हुई। इसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नए जिला अध्यक्षों को पार्टी को मजबूत करने की सीख दी। वहीं, दूसरी तरफ कई जिलों में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में भी हुआ। राहुल गांधी ने बताया कि पार्टी और संगठन को कैडर मजबूत करना है। उन्होंने कैडर मैनेजमेंट विषय पर नए जिला अध्यक्षों को टिप्स दिए। इस दौरान जिला अध्यक्षों को तीन महीने के भीतर जिले और ब्लॉक स्तर पर टीम बनाने का लक्ष्य दिया गया है।

पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं : कमलनाथ

दिग्विजय सिंह का बयान सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई।

फर्जी मतदाताओं का पता लगाएं कार्यकर्ता : उद्धव

» राज ठाकरे भी बोले- 'वोट चोरी' को लेकर कार्यकर्ता रहें सतर्क

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। मनसे और शिवसेना (उबाठा) के गठबंधन की अटकलों के बीच दोनों के नेताओं ने 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया और अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से फर्जी मतदाताओं का पता लगाने के लिए मतदाता सूची की जांच करने को कहा। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल मतदाता सूचियों में हेरफेर के इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। पिछले साल 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में शिवसेना ने 20 सीट हासिल कीं, जबकि मनसे को एक भी सीट नहीं मिली।

शिवसेना ने कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव बीएमसी होने हैं जो काफी प्रभावशाली है। इस चुनाव के लिए शिवसेना (उबाठा) और मनसे के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में 40 से 42 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया था। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से फर्जी मतदाताओं का पता लगाने के लिए मतदाता सूची की जांच करने को कहा। वहीं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि वह 2016 से ही ''वोट चोरी'' का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, दोनों ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, तब निर्वाचन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी। मनसे प्रमुख ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच करने को भी कहा।

निर्वाचन आयोग तब सही है जब कांग्रेस जीतती है: रविशंकर प्रसाद

» भाजपा सांसद का राहुल गांधी पर हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि वे 'बेशर्मी' से झूठ फैला रहे हैं और निर्वाचन आयोग के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं। पटना में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि गांधी इन आरोपों के जरिए लोगों को 'गुमराह' करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'राहुल और तेजस्वी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। वे पीएम के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह अस्वीकार्य है।

प्रसाद ने पूछा, '2024 के लोस चुनाव में सपा ने यूपी में 37 सीट जीतीं, भाजपा ने 33 और कांग्रेस ने छह सीट हासिल कीं। तब भी यही निर्वाचन आयोग था। अगर लोग उन्हें वोट दें तो निर्वाचन आयोग ठीक है, लेकिन अगर वे हार जाते हैं, तो यह बुरा है। यह तर्क कैसे काम कर सकता है? महाराष्ट्र की ओर इशारा करते हुए प्रसाद ने कहा, 'क्या वहां भी वही निर्वाचन आयोग नहीं था' जहां कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीट जीतीं, भाजपा और शिवसेना ने नौ-नौ, तथा राकांपा ने आठ सीट जीतीं।

गरीबों को राशन नहीं देना चाहता केंद्र

» राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार में रार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब में आठ लाख राशन कार्ड काटने को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाए कि केंद्र ने पंजाब के 802493 राश कार्ड काटने की साजिश रची है। इससे राज्य के 32 लाख लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में पंजाब और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। सीएम के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पलटवार किया है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मान को सही तथ्य पेश करने चाहिए। केंद्र ने सिर्फ अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए बोला है। पंजाब सरकार अपना काम नहीं कर रही। अयोग्य लाभार्थियों पहचान करने के बजाए उनको समर्थन कर रही है। जोशी ने कहा कि सबसे पहले लाभार्थियों की अनिवार्य ई केवाईसी का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। केंद्र सरकार केवल राज्यों को इसे लागू करने के लिए कह रही है। पंजाब सरकार को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन बार अतिरिक्त समय दिया जा चुका है। पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1.41 करोड़ लाभार्थी हैं। इस अधिनियम के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

1.41 करोड़ लाभार्थियों में से किसी को भी नहीं हटाया है : जोशी

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने मंजूर किए गए 1.41 करोड़ लाभार्थियों में से किसी को भी नहीं हटाया है। केंद्र केवल राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है कि लाभार्थियों की पुनः जांच की जाए। इसके लिए केंद्र ने विभिन्न स्रोतों से जुटाए गए डेटा पॉइंट्स पंजाब सरकार को दिए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई योग्य लाभार्थी अब तक योजना से वंचित है तो उसे जोड़ा जा सके।

जीशान का कमाल, मेरठ ने लहराया परचम

» यूपी टी-20 लीग: नोएडा किंग्स को आसान मुकाबले में 41 रन से हराया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। गत विजेता मेरठ मावरिक्स ने नोएडा किंग्स को आसान मुकाबले में 41 रन से हराते हुए यूपी टी-20 लीग में पूरे अंक प्राप्त किए। मेरठ के 184 रन के जवाब में नोएडा की टीम नौ विकेट खोकर 143 रन बना सकी। मुकाबले में मेरठ टीम में शामिल लखनवी स्पिनर जीशान ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए महज 17 रन देकर चार बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई।

इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे मेरठ ने 34 रन के योग पर दोनों सलामी बल्लेबाज खो दिए। अक्षय पांच और स्वास्तिक 20 रन पर आउट हुए। तीसरे क्रम पर रितुराज शर्मा ने 19 गेंदों पर एक चौके और तीन छक्कों की मदद से 34 रन की तेज पारी खेली, जबकि कप्तान रिंकू सिंह (10) सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद दिव्यांश राजपूत ने 28 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्कों की मदद से नाबाद 53 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर मेरठ को 184 रन तक पहुंचाया। टीम ने ऋतिक वत्स ने 18 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 24 रन की उपयोगी पारी खेली।

जीशान ने दिए चार झटके

जवाब में नोएडा को पहले ही ओवर में दो झटके लगे, जब विशाल चौधरी ने शिवम चौधरी (0) और प्रियांशु पांडेय (0) को पवेलियन भेजा। एक समय टीम ने 65 रन पर पांच बल्लेबाज खो दिए। निचले क्रम में प्रशांत वीर ने 39 और कर्ण शर्मा ने 37 रन बनाकर वापसी का प्रयास किया, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम लक्ष्य से 41 रन पिछड़ गई। मेरठ की ओर से जीशान अंसारी ने चार और विशाल चौधरी व कार्तिक त्यागी ने दो-दो विकेट हासिल किए।

सरकार ने देश के युवाओं के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए : राहुल

» नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल दागे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपार जनसमूह जुड़ रहा है। इस दौरान राहुल गांधी पूरी आक्रामकता से एनडीए सरकार पर हमले कर रहे है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर युवाओं को रोजगार और विकास से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के युवाओं के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और देश का धन चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है।

इसी दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार में आकर खुद देखना चाहिए कि किस तरह जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यात्रा के दौरान छोटे-छोटे बच्चे तक 'वोट चोर गद्दी छोड़' जैसे नारे लगा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि चुनावी धांधली को लेकर लोगों में जागरूकता और आक्रोश दोनों बढ़ रहा है।

राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि वे अपने मताधिकार को लेकर सजग रहें और किसी भी तरह की चुनावी गड़बड़ी बर्दाश्त न करें। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और देश की मौजूदा परिस्थितियों के प्रति जागरूक करना है।

राहुल ने खुद चलाई बाइक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी वोट अधिकार यात्रा के आठवें दिन की शुरुआत रविवार को पूर्णिया जिले से की। यात्रा की शुरुआत बाइक पर हुई, जिसमें वे खुश्कीबाग से निकलकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग और सिटी इलाके से गुजरते हुए कसबा और अररिया होते हुए नरपतगंज तक पहुंचे। राहुल गांधी पूर्णिया के गौरा मोड़ स्थित ठहराव स्थल पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने टेंट सिटी और पंडाल परिसर में रात गुजारी, जिससे विपक्षी एकजुटता का मजबूत संदेश गया। राहुल गांधी ने गौरा पंचायत से एक खुली जीप में यात्रा की शुरुआत की और बेलौरी पहुंचे। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर खुश्कीबाग से लाइन बाजार, रामबाग और अन्य इलाकों से होते हुए अररिया की ओर रवाना हुए। इस दौरान सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी।

एक झलक पाने के लिए लोगों ने किया घंटों इंतजार

राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे। छोटे बच्चे भी सड़क किनारे खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि, वे बिना रुके अररिया की ओर रवाना हो गए, जिससे कई लोग उनसे न मिल पाने के कारण निराश दिखे।

राहुल गांधी के साथ खड़ी है आम जनता

» 59 प्रतिशत लोग चुनाव आयोग पर लगाए विपक्ष के आरोपों से सहमत

» चुनाव आयोग बनाम नेता प्रतिपक्ष! सामने आया बड़ा सर्वे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। इसी के मद्देनजर इन दिनों कांग्रेस बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रही है। हालांकि, विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बीते दिनों चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इसी पीसी को लेकर वोट वाइब की तरफ से एक सर्वे किया गया।

इस सर्वे में विपक्ष के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर लोगों से सवाल पूछे गए कि इस पूरे मसले पर उनकी क्या राय है। इसमें 34 प्रतिशत लोगों ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जबकि 28 प्रतिशत लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग जवाब देने में विफल रहा है। सर्वे के मुताबिक 18 प्रतिशत लोगों का मानना है कि कुछ जवाब दिए गए हैं, जबकि कुछ सवालों के जवाब देना बाकी है। वहीं 20 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ 34 प्रतिशत लोग ही चुनाव आयोग के पक्ष में हैं, वहीं कुल 46 प्रतिशत लोग या तो चुनाव आयोग से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं या तो पूरी तरह से पक्ष में नहीं हैं।

इसी मुद्दे पर बीते दिनों सी वोटर ने भी सर्वे किया था। इसमें 59 प्रतिशत लोग चुनाव आयोग पर लगाए राहुल गांधी के आरोपों से सहमत दिखे, जबकि 34 प्रतिशत लोग चुनाव आयोग के समर्थन में नजर आए। वहीं, 67 प्रतिशत लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, जबकि 13 प्रतिशत लोग इससे सहमत नहीं हैं।

हिम्मत है तो देश के हर थाने में मेरे ऊपर केस दर्ज करवाए भाजपा : तेजस्वी यादव

» राजद नेता ने एनडीए सरकार को दी चुनौती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज होने के मामले पर सियासत जारी है। अब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि जुमलों की दुकान कहने पर खड़क्करने वालों मेरी बात सुन लो। यह दुकान ही नहीं बल्कि झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर बाजार है।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार का लाल है। मैं आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर हिम्मत है तो देश के हरेक राज्य के हरेक थाने में केस दर्ज करवाओ। आप लोग सबको अपने जैसा डरपोक समझते हो, हम बिहारी हैं बिहारी, ठेठ बिहारी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह लोग वोट चोर चुनाव में वोट चुरा सरकार बना लेते है। 20 वर्षों से सत्ता का मजा ले रहे भ्रष्टाचारियों को गणतंत्र की जननी बिहार से गणतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। इस बार लड़ेंगे भी, रोकेंगे भी और जीतेंगे भी। उन्होंने दावा किया गया कि हमारे संग समूचा बिहार खड़ा है। हमलोग किसी वोट का अधिकार नहीं छीनने देंगे।

सरकार को गाइडलाइन बनाने का सुप्रीम आदेश

दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर मांगें माफी कॉमेडियन, अल्लाहबादिया और समय पर भड़की कोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन्स और यूट्यूबर्स को सख्त निर्देश देते हुए दिव्यांगों पर आपत्तिजनक कंटेंट ना बनाने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा कोई कंटेंट बनाया गया है तो तुरंत इसके लिए माफी मांगी जाए। स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के मामले से जोड़ते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा कभी भी हुआ तो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आदेश दिया है कि वो दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए अपने पॉडकास्ट और कार्यक्रमो में सार्वजनिक माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगों का अपमान करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही क्यों न हों। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयानों और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाएं, जिनमें दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों का मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें नीचा दिखाया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के लिए नियम बनाते समय जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि सभी पक्षों की राय लेकर व्यापक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी ऐसे कमर्शियल कंटेंट पर लागू नहीं हो सकता, जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हों। इसके साथ ही कोर्ट ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो के होस्ट समय रैना की माफी पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पहले खुद का बचाव करने की कोशिश की थी, फिर माफी मांगी।

इन्फ्लुएंसर्स को हलफनामा देना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर्स से कहा कि वो हलफनामा दाखिल करें, जिसमें यह बताया जाए कि वो अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने में कैसे करेंगे। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल इन्फ्लुएंसर्स को हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते वो दिए गए निर्देशों का पालन करें।

शाह की टिप्पणी पर भड़के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

» 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने की गृहमंत्री की निंदा

» उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार पर दिया था बयान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने सलवा जुडूम फैसले को लेकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को ''दुर्भाग्यपूर्ण'' करार दिया । उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर सहित 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने यह भी कहा कि एक उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा शीर्ष अदालत के फैसले की ''पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या'' से न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।

शाह ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी पर नक्सलवाद का ''समर्थन'' करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं आता, तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक ही खत्म हो गया होता। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक, न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा, न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर शामिल हैं। शाह ने केरल में कहा था, '' सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की।

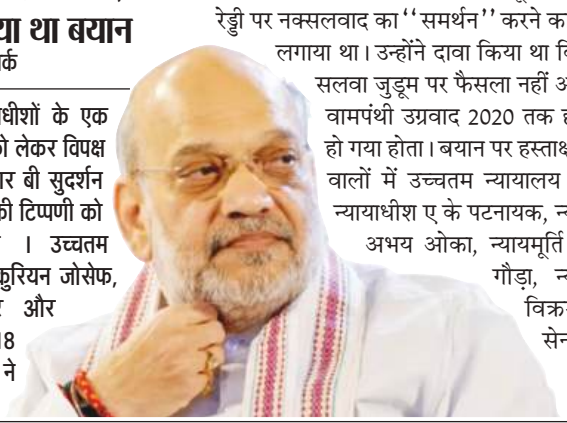

सलवा जुडूम मामले में गलत व्याख्या किया : पूर्व न्यायाधीश समूह

इन न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया, ''सलवा जुडूम मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यह फैसला न तो स्पष्ट रूप से और न ही लिखित निहितार्थों के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कहा, किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच सकता है।''

प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

» राजधानी में कमजोर पड़ेगा मानसून

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दोबारा सक्रिय हुए मानसून के बाद बीते तीन दिनों में प्रदेश के दक्षिणी और तराई इलाकों में कहीं भारी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के पूर्वी और तराई के 30 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 26 अगस्त से अगले पांच दिनों के लिए मानसूनी बारिश में कमी आएगी।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कि 25 अगस्त को यूपी के पूर्वी और तराई इलाके के 30 जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश के संकेत हैं। 26 अगस्त से अगले चार-पांच दिनों के लिए मानसूनी बारिश धीमी पड़ेगी। राजधानी में बादलों की सक्रियता से रविवार को हजरतगंज, महानगर, इंदिरानगर, गोमतीनगर, आलमबाग आदि इलाकों में छिटपुट बारिश व बूंदाबांदी देखने को मिली। बारिश के पहले और बाद में बादलों के चलते धूप-छांव का खेल भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी छिटपुट बारिश व बूंदाबांदी के संकेत हैं।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। महाराष्ट्र कार्यालय :- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 । Email: daily4pm@gmail.com । website: www.4pm.co.in । RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।